e Newsletter

31st issue

CMAR

CITY MANAGERS' ASSOCIATION RAJASTHAN

Promoting Excellence In City Management...

CMAR 31st e-Newsletter Issue

Editor in Chief:	**Dr. Manjit Singh, IAS** (Principal Secretary, LSGD, GoR)
Editorial Board:	**Shri Pawan Arora, IAS** (Director cum Joint Secretary, LSGD, GoR)
Editorial & Compilation:	**Dr. Himani Tiwari** (Coordinator, CMAR) **Mr. Sharawan Kumar Sejoo** (Research Assistant, CMAR)
Digital Typesetting:	**Mr. Arjun Pal** (IT Expert, CMAR)
CMAR Team:	**Mr. Sandeep Nama** (Research Investigator, CMAR) **Mr. Sitaram Verma** (Assistant, CMAR)

Our sincere thanks to:

Shri Mukesh Kumar Meena (RAS)	(Add. Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Dr. Virendra Singh (RAS)	(Dy. Director (Administration), Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Hulas Ray Pawar (R.Ac.S)	(Chief Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri R.K. Vijayvargia	(Additional Chief Town Planner, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
Shri Brijesh Pareek	(PRO, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)

For suggestions/feedback please write to:

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies

G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,

Telefax: 0141-2229966, website: www.cmar-india.org, Email: cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/

Contents

स्वच्छ सर्वेक्षण—2018 देश में 4 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ :स्वच्छता सर्वेक्षण—2018 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन	1
मुख्यमंत्री ने विश्व खाद्य दिवस पर 51 स्मार्ट अन्नपूर्णा वैन को दिखाई हरी झण्डी	4
नगर निगम और श्रीकृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट के बीच एमओयू	6
नगर निगम जयपुर का नया प्रयोग :शहर के कचरे से बने कम्पोस्ट खाद का नगर निगम जयपुर के उद्यानों में होगा उपयोग	8
फुलेरा, बगरू एवं साम्भर नगरपालिकाएं बनी 'ओडीएफ' :नगरपालिकाओं के 331 में से 289 वार्ड 'ओडीएफ' घोषित	9
दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार	10
कचरा दिखे तो ऐप पर डालें फोटो, नगरीय निकाय करवाएगी सफाई	11

स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 देश में 4 जनवरी, 2018 से प्रारम्भ

स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 500 शहरों (1 लाख और उससे अधिक आबादी वाले) में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान प्रारम्भ होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 की जानकारी देने के लिए सोमवार 18 सितम्बर, 2017 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल क्लार्क्स आमेर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग में किया गया।

इस अवसर पर नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने कहा कि स्वच्छता के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। उन्हें यह अहसास करना होगा कि यह शहर हमारा है। हमें इसे स्वच्छ रखना है। उन्होनें कहा कि आज विकास कार्यो की होड़ लगी हुई है। हर नगरीय निकाय विकास कार्यो पर जोर दे रहा है। उन्होनें कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को टीम भावना से काम करते हुए अपने–अपने वार्डो, शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाना है तथा आने वाले वर्ष में 4 जनवरी से प्रारम्भ होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर/प्रदेश को अव्वल बनाना है। उन्होनें बताया कि प्रदेश में सर्वे अनुसार 4.30 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयो का निर्माण किया जाना है। जिसके तहत अब तक स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर 420718 आवेदन अपलोड कर दिये गये है। जिसमे से 329268 आवेदनो को प्रमाणित कर 302857 आवेदनो की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा स्वच्छ भारत पोर्टल के अनुसार कुल 281000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयो एवं 903 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयो का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 45 का कार्य प्रगतिरत है। प्रदेश की 32 नगरीय निकायो को खुले मे शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है तथा 38 नगरीय निकायो को अक्टूबर 2017 तक तथा शेष सभी नगरीय निकायो को दिसम्बर, 2017 तक खुले मे शौचमुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश के कुल 5300 वार्डो मे से 3885 वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं दिसम्बर, 2017 तक शेष वार्डो मे घर–घर कचरा संग्रहण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में अनुमानित 6400 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है उसमे से वर्तमान मे 610 टन प्रतिदिन कचरा प्रोसेसिंग किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के परिसंस्करण एवं निपटान के लिए प्रदेश के 16 शहरो मे प्रोसेसिंग प्लांट के लगाये जा रहे है। यह सभी प्लान्ट मार्च 2018 तक तैयार हो जायेंगे। जिनमें अनुमानित 1500 टन प्रतिदिन कचरा प्रोसेसिंग हो सकेगा। जयपुर एवं जोधपुर मे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाये जा रहे है। जिनमे अनुमानित 1000 टन प्रतिदिन कचरे से लगभग 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। जो मार्च 2018 तक तैयार किये जायेगे।

अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण श्री श्रीराम वेदरे मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में गत 3 वर्षो से अभियान के तहत ऐतिहासिक एवं परम्परागत जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के प्रदेश के 66 शहरों को जोड़ा गया तथा वहॉ स्थित हैरिटेज एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया गया। उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) से जुड़े 66 शहरों में स्थित सभी बावड़ियों को जीर्णोद्धार योजना से जोड़ा जाये यदि किसी बावड़ी के जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है तो संबंधित अधिकारी इस संबंध में लिखित रूप में निदेशालय को जानकारी प्रेषित करे। उन्होनें बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) के द्वितीय चरण में प्रदेश के 191 नगरीय निकायों को जोड़ा गया है तथा यहॉ स्थित सभी बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा सरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाये जा रहे है। उन्होनें कार्यशला में बावड़ियों व रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जीओ–टेगिंग किये जाने की विधि पर भी प्रकाश डाला।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ मनजीत सिंह ने कार्यशाला में कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 के बारे में निकाय प्रमुखों एवं अधिकारियों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होनें बताया कि सर्वेक्षण–2018 का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता मे उनकी भागीदारी एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है साथ ही इस सर्वेक्षण से नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने मे सुधार करना एवं सभी नगरीय निकायों में एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा को जागृत करना है। उन्होनें बताया कि राजस्थान सभी केन्द्रीय योजनाओं में अग्रणी है। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन में भी राजस्थान को आगे निकलना होगा।

निदेशक, स्वच्छता, डॉ आरूषि मलिक ने कार्यशला में स्वच्छता सर्वेक्षण–2018 पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में अब तक 27 लाख से अधिक घरेलू शौचालयों को निर्माण किया जा चुका है। उन्होनें कहा कि जब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त किये जाने में आगे बढ़ रहे है, तो ऐसे में शहरी नगरीय निकायों को भी प्रयास करके अपने–अपने क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाना होगा।

इस अवसर पर निदेशक एवं सुयक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2018 से प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण

– 2018 प्रारम्भ किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में प्रदेश की 191 नगरीय निकाय भाग लेंगी। उन्होनें कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए नये पैरामीटर तैयार किये गये है। जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या/ राज्यों की राजधानी के 500 शहरों की रैकिंग ऑल इण्डिया लेवल पर की जायेगी। जिसमें राज्य के 29 शहरी सम्मिलित होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 3541 शहरों की रैकिंग राज्य एवं जोन स्तर पर की जायेगी। जिसमें राज्य की 162 नगरीय निकाय सम्मिलित होंगी।

केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट श्री वैभव राव ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें कुल अंकों में से म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए 35 प्रतिशत, प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत एवं नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के लिए म्यूनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए कुल 1400 अंको का बटवाया किया जायेगा, जिनमें ठोस कचरे का परिवहन एवं एकत्रिकरण के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), ठोस कचरे का प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए 25 प्रतिशत (350 अंक), स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त 30 प्रतिशत (420 अंक), सूचना–शिक्षा एवं संचार व्यवहार में बदलाव के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक), क्षमता सवंर्द्धन के लिए 5 प्रतिशत (70) एवं नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रक्रिया के लिए 5 प्रतिशत (70 अंक) दिये जायेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण – 2018 के लिये स्वतंत्र सत्यापन के लिए इन्डीकेटर्स की प्रगति सही नहीं होने के स्थिति में नेगेटिव मार्किंग भी की जा सकेगी।

उन्होनें बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2018 के तहत प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए जो सर्वेक्षण पद्धति निर्धारित की गयी है उसमें 1200 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (360 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (420 अंक) निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 1400 अंकों में प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 30 प्रतिशत (420 अंक), नागरिक प्रतिक्रिया के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक), सर्विस लेवल प्रोग्रेस के लिए 35 प्रतिशत (490 अंक) निर्धारित किये गये है।

उन्होनें कहा कि प्रदेश को खुले में शौच मुक्त बनाये जाने के लिए दिसम्बर 2017 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के सभी वार्डो/शहरों को दिसम्बर, 2017 से पूर्व खुल में शौच से मुक्ति के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध रूप से आवश्यक शौचालयों का निर्माण तेजी से करते हुए निर्धारित समयावधि में लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के तहत घर–घर कचरा संग्रहण/परिवहन, प्रसंस्करण एवं निपटान के सभी कार्य करने होंगे।

कार्यशाला में परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी श्री प्रीतम बी. यशवंत ने नगरीय विकास कर एवं पॉलीसी रिफार्म, सम्पर्क पोर्टल पर अतिरिक्त निदेशक श्री मुकेश कुमार मीणा ने, दीनदयाल उपाध्यान शहरी आजीविका मिशन पर परियोजना निदेशक श्री एस.आर.मीणा ने, डेयरी बूथ फॉर वूमन विषय पर निदेशक विधी श्री अशोक सिंह ने एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के वेब एवं मोबाईल ऐप्लीकेशन पर उपनिदेशक एसीपी श्री उमेश जोशी ने प्रस्तुतीकरण दिया।

मुख्यमंत्री ने विश्व खाद्य दिवस पर 51 स्मार्ट अन्नपूर्णा वैन को दिखाई हरी झण्डी

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने विश्व खाद्य दिवस के मौके पर 16 अक्टूबर, 2017 को गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना के दूसरे चरण की अजमेर से शुरूआत की। उन्होंने अजमेर के विजयलक्ष्मी पार्क में वाल्मिकी एवं मुस्लिम समाज की महिलाओं को अपने हाथ से निवाला खिलाकर इस योजना का श्रीगणेश किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 51 स्मार्ट मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें विभिन्न शहरों के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 13 दिसम्बर तक प्रदेश के सभी 191 स्थानीय निकायों में 500 स्मार्ट मोबाइल वैनों के माध्यम से मात्र 5 रुपये में नाश्ता तथा मात्र 8 रुपये में दोपहर व रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना में साधारण रसोई वैन के माध्यम से नाश्ता एवं भोजन वितरित किया जा रहा था लेकिन अब स्मार्ट रसोई वैन से भोजन वितरित होगा। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की देश की इस पहली और अनूठी योजना को हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य भी लागू कर रहे हैं।

भोजन वितरण से लेकर फीडबैक तक की जानकारी ऑनलाइन

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में स्मार्ट किचन स्थापित की जा रही हैं। जहां अधिकतर काम मशीनों के सहयोग से किया जाता है ताकि भोजन की शुद्धता एवं गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। अब भोजन बनाने और वितरित करने की जानकारी के साथ लाभार्थी के फीडबैक तक सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। **ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। मोबाइल वैन से भोजन करने वाला व्यक्ति किसी भी समय वैन पर मौजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये खाने की क्वालिटी, वजन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक इस कंट्रोल रूम को दे सकेगा।** मोबाइल वैन को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे कि उसकी रीयल टाइम लोकेशन पता चल सके।

भामाशाहों से की सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना के लिये प्रतिवर्ष 325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने संस्थाओं, दानदाताओं और आमजन से इस योजना के संचालन में सहयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डोनेशन के लिये ऑनलाइन व्यवस्था है। भोजन पर होने वाले खर्च की पूरी जानकारी मोबाइल वैन तथा स्थानीय निकाय के कार्यालय में उपलब्ध होगी। कोई भी भामाशाह जन्मदिवस, वर्षगांठ जैसे मौके पर एक दिन, दो सप्ताह, एक महीना, 6 महीना जैसे किसी भी समयावधि के लिये श्रद्धानुसार सहयोग दे सकता है।

सभी विधायकों और मंत्रियों ने सहयोग की घोषणा की

श्रीमती राजे की अपील पर संसदीय सचिव श्री शत्रुघ्न गौत्तम ने घोषणा की कि वे एक वर्ष तक अन्नपूर्णा रसोई योजना में पैसा देकर अपने विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में लोगों को भोजन करवाएंगे। फिर क्या था, शिक्षा राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती अनिता भदेल, संसदीय सचिव श्री सुरेश रावत और विधायक श्री भागीरथ चौधरी एवं श्री शंकरसिंह रावत ने भी अपने–अपने विधानसभा क्षेत्रों में एक वर्ष तक अन्नपूर्णा रसोई वैनों के जरिये भोजन वितरण के लिये सहयोग राशि देने की घोषणा की। अजमेर के मेयर श्री धर्मेन्द्र गहलोत ने स्थानीय अस्पताल में मोबाइल भोजन वैन के लिये एक वर्ष और अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शिव शंकर हेड़ा ने 6 माह के लिये सहयोग राशि देने की घोषणा की। वैश्य समाज, अन्य संस्थाओं और भामाशाहों ने भी सहयोग की पेशकश की, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें स्थानीय निकाय विभाग से अपनी पेशकश दर्ज कराने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अजमेर शहर में 15 हजार अतिरिक्त एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे दीपावली के समय पूरा शहर रोशनी से जगमग हो सकेगा। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री श्री श्रीचंद कृपलानी, धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकारसिंह लखावत, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री मंजीत सिंह, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री पवन अरोड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं आमजन उपस्थित थे।

नगर निगम और श्रीकृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट के बीच एमओयू

हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र के लिए दस करोड़ का विशेष अनुदान
गौसेवा की अनूठी मिसाल बनाएंगे–मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र को राज्य सरकार देश में गौ सेवा के एक आदर्श केन्द्र के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने इसके लिए 28 अक्टूबर, 2017 को गोपाष्टमी पर जयपुर नगर निगम को दस करोड़ रूपए का विशेष अनुदान देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र में गौवंश की पूजा की तथा गायों को गुड़ एवं चारा खिलाकर आमजन को गौसेवा का पावन संदेश दिया।

गौ सेवा सरकार की ही नहीं, सबकी जिम्मेदारी

यहां गौपूजन एवं अन्नकूट प्रसादी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा हमारी धार्मिक भावना और आस्था से जुड़ा ऐसा विषय है जो मात्र सरकार ही नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। राज्य सरकार इस दिशा में समर्पित भाव से काम कर रही है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि हिंगोनिया में हमें गौ वंश के संरक्षण में अधिक सफलता मिल रही है। उन्होंने इसके लिए हरे कृष्णा मूवमेंट को बधाई दी।

पॉलीथिन और गौ सेवा एक साथ नहीं

उन्होंने पॉलीथिन के उपयोग के कारण गौ वंश पर पड़ रहे दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गौसेवा और पॉलीथिन एक साथ नहीं चल सकती। इसीलिए हमने पॉलीथिन को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि वे स्वयं पॉलीथिन का उपयोग बंद करें तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यही सच्ची गौ सेवा होगी। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास मंत्री, कृषि मंत्री तथा जयपुर महापौर को निर्देश दिए कि वे शहरी क्षेत्र में हर सप्ताह पॉलीथिन की रोकथाम के लिए गतिविधियां आयोजित करें।

मोबाइल एप लॉन्च

मुख्यमंत्री ने हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र पर आधारित 'श्रीकृष्ण बलराम गौ शाला' मोबाइल एप लॉन्च किया। इस एप में गौ वंश तथा उनके संरक्षण से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई हैं। श्रीमती राजे ने कहा कि इस एप के जरिए गौ सेवकों को गौ सेवा से जुड़ने और अपडेट रहने का माध्यम मिलेगा।

19 वर्ष के लिए एमओयू

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र के प्रबंधन के लिए जयपुर नगर निगम तथा हरे कृष्णा मूवमेंट से संबद्ध श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट के बीच 19 वर्ष के लिए एमओयू का आदान–प्रदान हुआ। नगर निगम आयुक्त श्री रवि जैन तथा ट्रस्ट के आर. गोविन्ददास प्रभुजी ने एमओयू का आदान–प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गौ पुनर्वास केन्द्र में सहयोग करने वाले गौ सेवकों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने यहां गायों को पोषक चारा उपलब्ध कराने के लिए टोटल मिक्स राशन मशीन (टीएमआर) तथा कृषक खाद मेला ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नवीनीकृत ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया तथा आधुनिकतम चिकित्सा सुविधाओं से युक्त आईसीयू का अवलोकन भी किया। उन्होंने हिंगोनिया गौ पुनर्वास केन्द्र की 7 विकास परियोजनाओं की शुरूआत की।

गौ संवर्धन के सुखद परिणाम सामने

इससे पहले श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट के आर. गोविन्ददास प्रभुजी ने कहा कि पिछले एक साल में हिंगोनिया में गौ धन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आए हैं। यहां की गायों से प्रतिदिन दूध का उत्पादन 150 लीटर से बढ़कर 2400 लीटर प्रतिदिन हो गया है। यहां लाए जाने वाले गौवंश की मृत्यु दर को रोकने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है।

नगर निगम जयपुर का नया प्रयोग

शहर के कचरे से बने कम्पोस्ट खाद का नगर निगम जयपुर के उद्यानों में होगा उपयोग

नगर निगम जयपुर आयुक्त श्री रवि जैन ने 01 नवम्बर, 2017 को उपायुक्त उद्यान को निर्देश दिए हैं कि सेवापुरा में पहुंचने वाले जयपुर शहर के कचरे से तैयार की गई कम्पोस्ट खाद का उपयोग नगर निगम जयपुर के उद्यानों में किया जाए। श्री जैन ने बताया कि इस कम्पोस्ट खाद का उपयोग नगर निगम जयपुर के उद्यानों में करने से उद्यानों की हरियाली में इजाफा होगा। इससे पेड़–पौधों में गुणवत्तापूर्ण अच्छी वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि इससे शहर के कचरे का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग हो सकेगा। साथ ही पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि यह खाद साधारण खाद से अधिक गुणवत्ता युक्त होती है।

आयुक्त श्री जैन ने उपायुक्त उद्यान को निर्देश दिए हैं कि गैराज शाखा से 4 डंपर नियमित रूप से लेकर सेवापुरा कम्पोस्ट प्लान्ट से कम्पोस्ट खाद परिवहन करवाकर नगर निगम जयपुर के उद्यानों में डलवाने का कार्य अतिशीघ्र शुरू करवाएं।

फुलेरा, बगरू एवं साम्भर नगरपालिकाएं बनी 'ओडीएफ'

नगरपालिकाओं के 331 में से 289 वार्ड 'ओडीएफ' घोषित

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में शौचालयों के निर्माण में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचा, जयपुर जिला स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत भी 'ओडीएफ' (खुले में शौच से मुक्त) होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जिला कलेक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने 04 अक्टूबर, 2017 के आयोजित बैठक में यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले की दस नगर पालिकाओं में फुलेरा, बगरू और साम्भर पूरी तरह 'ओडीएफ' (खुले में शौच से मुक्त) घोषित होने वाली पालिकाएं बन गई है। उन्होंने बताया कि जिले की नगर पालिकाओं के कुल 331 में से 289 वार्ड पूरी तरह 'ओडीएफ' हो गए हैं।

नगर पालिकावार 'ओडीएफ' वार्ड

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले की 10 नगर पालिकाओं के 'ओडीएफ' घोषित 289 वार्डों में से फुलेरा के 20 में से 20, बगरू के 25 में से 25 तथा साम्भर के भी सभी 20 वार्ड शामिल है। इसी प्रकार शाहपुरा के 25 में से 21 वार्ड, विराट नगर के 20 में से 17, कोटपूतली के 30 में 27, किशनगढ़ रेनवाल के 25 में 23, जोबनेर के 15 में 14, चौमूं के 35 में से 17 तथा नगर पालिका चाकसू के 25 में से 16 वार्ड ओडीएफ घोषित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि जिन नगर पालिकाओं में 'ओडीएफ' सम्बंधी कार्य शेष बचा है, वहां पर अधिशाषी अधिकारियों को प्रयासों में गति लाने के निर्देश दिए गए है। साथ ही सम्बंधित उपखण्ड अधिकारियों की इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए दैनिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए है।

दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार

स्वायत्त शासन विभाग दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) के माध्यम से रोजगार दिलवायेगा। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) के उपाध्यक्ष श्री गुजराल सिंह उपल के साथ एक एग्रीमेंट किया। इस अवसर पर दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के परियोजना निदेशक श्री एस.आर.मीणा, स्टेट मैनेजर डॉ वर्षा तनु तथा ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) के अधिकारी उपस्थित थे।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्री पवन अरोड़ा ने बताया कि ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) प्रदेश के 10,000 युवाओं को लीजिंग पार्टनर के रूप में रोजगार उपलब्ध करवायेगा। उन्होनें कहा कि दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आज इस संबंध में ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) से एक एग्रीमेंट किया गया है। ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) द्वारा बेरोजगार युवाओं को, जिनके पास कार का ड्राईविंग लाईसेंस है उन्हें 50 घण्टे का प्रशिक्षण एवं जिनके पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं है उन्हें 200 घण्टे का प्रशिक्षण मुम्बई व देश के अन्य शहरों में दिया जायेगा। इस दौरान प्रथम तीन माह में 14,000 रूपये एवं रहने की सुविधा तथा तीन माह पश्चात् 18,000 रूपये मासिक वेतन दिया जायेगा। इस दौरान जहॉ पर सीएनजी द्वारा वाहन चलाये जाते है वहॉ 11 घण्टे का कार्य तथा जहॉ पर पेट्रोल अथवा डीजल से वाहन चलाया जाता है वहॉ 12 घण्टे कार्य करना होगा। उन्होनें बताया कि शहरी गरीब युवाओं को बिना किसी शुल्क के ओला फ्री टेक्नोलॉजी (ओला टैक्सी) द्वारा प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।

कचरा दिखे तो ऐप पर डालें फोटो, नगरीय निकाय करवाएगी सफाई

नगरीय निकाय अब केन्द्र सरकार की स्वच्छता ऐप से जुड़ गई है। ऐप की विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से गंदगी या जलभराव की फोटो खींचकर शिकायत दर्ज करा सकता है। निकाय कर्मचारियों को इसका शिकायत का निराकरण भी तय समय में कराना पड़ेगा। नगरीय निकाय को इसके लिए शासन स्तर से स्वच्छता के लिए सक्रिय रहने के नंबर मिलेंगे। इसलिए नगरीय निकाय इस शिकायत को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगी।

शिकायत कर सकेंगे रि–ओपन

ऐप में आमजन द्वारा डाली गई फोटो के बाद भी संतुष्ट नहीं होन पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को रि–ओपन कर सकेगा। जब सफाई हो जाएगी तो फोन लगाकर पूछा जाएगा कि समस्या हल हुई या नहीं।

ऐसे करें डानलोड

स्वच्छता संबंधी कोई शिकायत हो तो पोस्ट ए कंप्लेंट पर क्लिक या टच करें। आप अपने स्मार्ट फोन (जिसमें इंटरनेट हो) उसके प्ले स्टोर, मार्केट, ऐप स्टोर, (एंड्राइड, आईओएस) में जाएं। प्ले स्टोर पर खोजें swachhta-MoHUA और उसे डाउनलोड कर इंस्टाल करें। फिर ओपन करें, भाषा का चयन करें, फोन नंबर डालें। उसके बाद चाहें तो अपनी प्रोफाइल में फोटो, जानकारी आदि अपडेट करें।

ऐसे अपलोड कर सकेंगे फोटो

आपको कहीं गंदगी दिखे या स्वच्छता संबंधी कोई शिकायत हो तो स्वच्छता एप को ओपन करने के बाद पोस्ट ए कंप्लेंट पर क्लिक करें फिर लोकेशन ऑन करने के लिए ओके करें। फिर चित्र खीचें या पहले से खींचे गए चित्र को गैलरी से चुनें और ओके करें। केटेगरी (प्रकार) चुनें की खींचा गया चित्र किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। फिर जगह और स्थान का नाम लिखें और पोस्ट पर क्लिक करें। स्वच्छता ऐप पर जैसे ही आप किसी भी समस्या की शिकायत करेंगे तो तुरंत उसका मैसेज आ जाएगा और जब सफाई हो जाएगी तो शिकायतकर्ता को फोन लगाकर पूछा जाएगा समस्या हल हुई या नहीं।

CMAR

Our Partners

National Institute of Urban Affairs

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICMA
International City/Country Management Association

USAEP
United States-Asia Environmental Partnership

City Managers' Association Rajasthan, Room No. 410, Directorate of Local Bodies
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,

Telefax: 0141-2229966
website: www.cmar-india.org
Email: cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at:
http://cmar-india.org/